जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

बीकानेर

Rashtradoot

फोनः- 2200660 फैक्स : 0151-2527371 वर्षः 44 संख्याः 73 प्रभात बीकानेर, शुक्रवार 7 अक्टूबर, 2022 डाक प.स.बीकानेर/045/2020-22 पृष्ठ 8 मूल्य 2.50 रू.

यूरेशियन बीवर्स (ऊद बिलाव की एक प्रजाति) को इंग्लैंड में यूरोपियन प्रोटैक्टेड प्रजाति के रुप में मान्यता दी गई है, अब इसे पकड़ना, मारना, चोट पहुंचाना या परेशान करना गैर कानूनी हो गया है। इस कदम से, बीवर्स को नियंत्रित करने के लिए पूर्व में जो तरीके काम में लिए जा रहे थे उनपर अंकुश लग गया है। अब भूस्वामी ''नैचुरल ईग्लैंड'' संस्था से लाइसैंस लिए बिना बीवर के बिल या बांध को तोड़ नहीं सकेंगे। वन्य जीव संगठनों ने इस कदम की तारीफ की है। उनका कहना है कि, बीवर्स द्वारा बनाए गए बांधों से पर्यावरण की बड़ी सहायता हुई है, इससे पानी साफ रहता है तथा बाढ़ व अकाल का खतरा भी कम हो जाता है। बीवर ट्रस्ट नामक संस्था की चीफ एग्ज़िक्युटिव सैंड्रा किंग ने कहा कि, बीवर ने हमारी जमीन के इकोसिस्टम की बड़ी सहायता की है और यह कदम इंग्लैण्ड में इस प्रजाति के लिए एतिहासिक है। पूर्व में नैशनल फार्मर्स यूनियन ने बीवर्स को संरक्षण प्रदान करने पर आपत्ति जताई थी। उनका कहना था कि बीवर्स के बनाए बांधों से खेतों में बाढ़ का खतरा हो सकता है। यह संरक्षण उन प्रजातियों को दिया जाता है जो संकटग्रस्त हैं, संकट के कगार पर हैं या दुर्लभ हैं और पूरे यूरोप में खतरे से जूझ रही हैं। यूरेशियन बीवर कभी बड़ी तादाद में मिलते थे, पर 400 साल पहले अंधाधुंध शिकार की वजह से लुप्त हो गए। इन्हें ब्रिटेन में कई स्थानों पर पुनः बसाया गया। वर्ष 2009 में स्कॉटिश बीवर ट्रायल प्रॉजैक्ट के तहत स्कॉटलैण्ड में भी इन्हें बसाया गया, जो कि यू.के का पहला अधिकृत मैमल्स रीइन्ट्रोडक्शन प्रॉजैक्ट था। बाद में वर्ष 2019 में बीवर्स को स्कॉटलैण्ड में संरक्षित प्रजाति का स्टेटस दिया गया। वाइल्डलाइफ ट्रस्ट्स, जिन्होंने पूरे यू.के. में बीवर्स छोड़े जाने का काम देखा है, ने बीवर्स को संरक्षण देने की खबर पर खुशी जाहिर की है।

काफी संतुष्ट होकर पायलट दिल्ली लौटे, अपनी जयपुर यात्रा के बाद

-विशेष प्रतिनिधि द्वारा-

जयपुर, 6 अक्टूबर। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी में मची राजनीतिक उथल-पुथल की थिओरैटिकल धुरी में अब बहुत महत्व इस बात का हो गया है कि, हाई कमान के, सचिन पायलट को राजस्थान का मु.मंत्री ''थोपने'' के प्रयास के विरोध में, शांति धारीवाल के निवास पर आखिर कितने विधायक मौजूद थे और इसी क्रम में कितने विधायकों ने अन्ततोगत्वा विधानसभा अध्यक्ष के घर जाकर विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया। ''लॉजिकली'' इस प्रश्न का सीधा जवाब विधानसभा अध्यक्ष के पास होना चाहिये।

पर, न तो, वे कन्फ्यूज़न हटाने के लिये, स्वेच्छा से बता रहे हैं और न ही हाई कमान उनसे सीधे ही पूछ रहा है। कन्फ्यूज़न दोनों पक्षों को माफिक आ रहा है। गहलोत तो गर्व से, छाती ठोक कर कह रहे हैं कि, 92 विधायक उनके साथ हैं। पर, इस दावे की मजबूती व सच्चाई स्थापित करने के लिये विधायकों की सूची पेश करने में कोई रूचि नहीं दिखा रहा है गहलोत का खेमा। पर, मु.मंत्री, मु.मंत्री ही होता है, उनका पक्ष मीडिया में और ''मित्रता'' से प्रभावित मीडिया में ज्यादा बार और ज्यादा जोरों से सुनायी देता है और दिखता है। अतः ज्यादा ''प्रामाणिक'' लगता है।

कई ''स्वतंत्र चैनल्स'', जो ''सच्चाई'' की खोज में लगे हैं, ने इस बात के कई तर्क व प्रमाण पेश करने के प्रयास किए हैं कि, मु.मंत्री के खेमे के विधायकों की संख्या के बारे में प्रस्तुत दावे में दम या सच्चाई नहीं है। पर, आज तक इन ''खोजी पत्रकारिता'' से ''ओत-प्रोत'' चैनल्स को अपने आंकड़ों व तर्कों का मुख्यमंत्री खेमे से कोई पॉइन्ट-टु-पॉइन्ट, जवाब नहीं मिला है। पर क्यों? क्योंकि, ''बाड़ा'' तोड़ कर स्वेच्छा से होटलों में रहे विधायकों की भाँति इन मु.मंत्री समर्थक विधायकों की मजबूरी है कि वे, ''जायेंगे तो जायेंगे कहाँ?''

सचिन पायलट के लगभग तीन दिवसीय जयपुर प्रवास में, उनकी पार्टी के कई विधायक उनसे जयपुर में भी मिले तथा सम्पर्क किया, कभी परोक्ष रूप से या सीधा ही अपना ''मूक'' समर्थन जताने के लिये। खुल कर, सार्वजनिक रूप से मुखरित क्यों नहीं हो रहे? शायद, इसलिये कि, अभी से ''कलेजा खोलने से क्या लाभ'', जब पर्यवेक्षक पूछेंगे तो उनके कान में बता देंगे, हम किसके साथ हैं। अतः पहले पर्यवेक्षकों को आने तो दो, या उनके कार्यक्रम की घोषणा तो होने दो।

पर्यवेक्षक के कान में ही अपना मत उजागर करने की परम्परा हाई कमान को सूट करती है। गहलोत द्वारा मु.मंत्री के रूप में अपनी दूसरी पारी शुरू करने से पहले विधायकों की ''चॉइस'' जानने के लिये भी इसी पद्धति से रायशुमारी हुई थी तथा रायशुमारी का संचालन करने के लिये गुलाम नबी आज़ाद के नेतृत्व में टीम आयी थी। कांग्रेस विधायक दल में कुल 96 विधायक थे। रायशुमारी में गहलोत के पक्ष में 45-46 विधायकों ने राय दी, उनके उस चुनाव में प्रतिद्वंदी सी.पी. जोशी को अट्ठारह-बीस वोट मिले थे। बाकी विधायकों ने निर्णय हाई कमान पर छोड़ने की राय व्यक्त की थी। ऐसे विधायकों की संख्या लगभग तीस थी। हाई कमान का भी मन अशोक गहलोत को मु.मंत्री बनाने का था। अतः, चुनाव के बाद गहलोत के खेमे ने गहलोत के पक्ष के वोट व हाई कमान पर निर्णय छोड़ने वाले विधायकों की संख्या जोड़कर 70-75 वोट पाने का दावा किया। किसी ने इस दावे को चैलेन्ज नहीं किया: न तो हारे हुए प्रत्याशी के समर्थकों ने, न ही हाई कमान के प्रतिनिधि पर्यवेक्षकों ने और गहलोत के खेमे का चुनौती देने का सवाल ही नहीं उठता था। हाई कमान ने चुप्पी इसलिये रखी कि उनके मन की इच्छा पूरी भी हुई और उसकी क्या ''चॉइस'' थी यह स्पष्ट रूप से उजागर भी नहीं हुआ। हाई कमान को अपना खेल खेलने का पूरा मौका भी मिल गया था। यह तभी संभव है जब, कान में अपनी राय बताने की पद्धति का अनुसरण हो।

पर हाई कमान यह भी नहीं चाहता कि, उसकी ''चॉइस'' के सामने उसका प्रतिद्वंदी, ''चॉइस उम्मीदवार'' के बराबर का हो या उससे भारी हो। जैसा कि, मु.मंत्री बरकत साहब की असामयिक मृत्यु के बाद हुआ। जब विधायक दल की बैठक में रायशुमारी हुई तो, हाई कमान की पसंद रामनिवास मिर्धा को उनके प्रतिद्वंदी हरदेव जोशी से

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

उदित राज ने राष्ट्रपति मुर्मू के कथन पर व्यांगात्मक टिप्पणी की

- राष्ट्रपति मुर्मू, अपना संवैधानिक पद संभालने के बाद, पहली बार गुजरात यात्रा पर थीं तथा राज्यपाल द्वारा उनके लिए आयोजित नागरिक सम्मान समारोह को संबोधित कर रही थीं।
- राष्ट्रपति ने गुजरात की प्रशंसा करते हुए कहा था कि, गुजरात देश की आवश्यकता का 76 प्रतिशत नमक प्रड्यूस करता है तथा सारा देश गुजरात का नमक खाता है।
- उदित राज ने ''नमक खाने का अर्थ'' वफादारी से जोड़ा और आगे कहा, जब आदिवासी/एस.सी. का व्यक्ति देश के किसी उच्च पद पर पहुंच जाता है तो, अपना मूल भूल जाता है और चमचागिरी करने लगता है, राष्ट्रपति मुर्मू की भाँति।
- उदित राज पूर्व में भाजपा के सांसद थे तथा 2019 में भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं।

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के इस कथित बयान कि ''गुजरात देश का 76 प्रतिशत नमक उत्पादित करता है और यहां उत्पादित नमक का सभी भारतीय उपभोग करते हैं'' ने उलझन भरी स्थिति पैदान कर दी है, क्योंकि उनका बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और इसके परिणामस्वरूप भाजपा और कांग्रेस के बीच वाक् युद्ध छिड़ गया है।

मुर्मू, गत जुलाई माह में देश का शीर्ष संवैधानिक पद ग्रहण करने के बाद पहली बार गुजरात दौरे पर थीं और राज्यपाल आचार्य देवव्रत द्वारा अपने सम्मान में दिए गए स्वागत समारोह में संबोधन दे रही थीं। उन्होंने अर्थव्यवस्था के विभिन्न सैक्ट्र्स में गुजरात के योगदान की प्रशंसा करते हुए कहा कि पूरी दुनिया में इस राज्य के लोगों को उनकी मेहतन, समर्पण और समाज सेवा के लिए जाना जाता है।

राष्ट्रपति ने कहा कि ''दुग्ध उत्पादन और उपभोग में भारत प्रथम स्थान पर है। श्वेत क्रांति की शुरुआत करने में गुजरात की दुग्ध सहकारी समितियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुजरात देश के 76 प्रतिशत नमक का उत्पादन करता है। यह कहा जा सकता है कि सभी देशवासी गुजरात का नमक खाते हैं।''

भाजपा के पूर्व सांसद एवं वर्ष 2019 में भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए उदित राज ने मुर्मू के बयान को ''चमचागिरी की हद'' बताया- क्योंकि मुर्मू बयान का यह अर्थ निकाला जा सकता है कि देश के लोगों को इस राज्य के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस कथित अपमानजनक टिप्पणियों को लेकर कांग्रेस के इस नेता को एक नोटिस भेजने का निर्णय लिया।''

उदित राज की पूर्व पार्टी भाजपा ने ''देश की प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति'' के अपमान को लेकर उनसे और कांग्रेस से क्षमा मांगने को कहा।

उदित राज तब से ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के गृह राज्य में राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा हाल ही दिए गए भाषण से संबंधित अपने ट्वीट का बचाव कर रहे है। मुर्मू ने अपने भाषण में कहा था कि ''गुजरात देश का 76 प्रतिशत नमक उत्पादित करता है, यह कहा जा सकता है कि देश के सभी लोग गुजरात का नमक खाते हैं।

यह राज्य, वास्तव में नमक का एक बड़ा उत्पादक है, लेकिन आलोचक जैसे कि उदित राज ''नमक खाते हैं,'' जैसे शब्दों से चिढ़े हुए हैं। यह एक हिंदी कहावत है, जो वफावादी की प्रतिबद्धता को इंगित करती है।

उदित राज ने उनसे कहा कि वे सिर्फ नमक पर ज़िंदा रहें और ऐसी कोशिश करें क्योंकि वंचित समुदायों के लोगों को अक्सर ऐसा ही कुछ करना पड़ता है। राष्ट्रपति के ट्विटर हैण्डिल ने उनके भाषण को साझा किया था।

भाजपा की चिल्ल-पों के बाद राज

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

गोवा फिल्म फैस्टिवल

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर। गोवा में 20 से 28 नवम्बर तक आयोजित होने वाले ''इन्टरनेशनल फिल्म के फेस्टिवल ऑफ इंडिया (आई.एफ. एफ.आई.) मीडियाकर्मियों के लिये अधिकृत रुप से पूरे सम्मान के साथ खोला जा रहा है। राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय मीडिया को ऑनलाइन प्राधिकृत किया जाना शुरु हो गया है। ऑनलाइन मान्यता 5-6 नवम्बर के बीच आधी रात तक, और पूरी तरह सही कहा जाये तो नवम्बर को रात 11:59:59 तक प्राप्त की जा सकेगी।

- 20 से 28 नवम्बर तक चलने वाले इस फिल्म फैस्टिवल के लिए राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय पत्रकारों को ऑनलाइन स्वीकृति देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

इससे मीडियाकर्मियों को यह अवसर मिलेगा कि वे इस सिनेमाई समारोह एवं प्रेरणा के लिये पर्यटन प्रधान राज्य गोवा में इकट्ठे हो रहे सुप्रसिद्ध

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

महेश जोशी 26 अक्टूबर तक समय चाहते हैं, नोटिस का जवाब देने के लिये

उनका दावा है कि, ए.आई.सी.सी. की अनुशासन समिति का कारण बताओ नोटिस उन्हें आज, 6 अक्टूबर को ही प्राप्त हुआ है

- दो और आरोपित, शांति धारीवाल व धर्मेन्द्र राठौड़ को शायद नोटिस पहले मिल गये थे तथा चर्चाओं के अनुसार, वे अपना जवाब/स्पष्टीकरण भेज चुके हैं।
- क्या महेश जोशी का जवाब नहीं देना, अनुशासन समिति की कार्यवाही लम्बी खींचना है।
- अनुशासन की कार्यवाही जब तक पूरी नहीं होती तो क्या मुख्यमंत्री को बदलने का कार्यक्रम भी टल जाता है? जैसा कि चर्चित है, ज्योतिष की दृष्टि से 23 अक्टूबर तक का समय मु.मंत्री के लिये शुभ नहीं है, अतः अगर यह, 23 अक्टूबर तक का समय टल जाता है तो मु.मंत्री सेफ हो जाते हैं।

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर। जिस दिन कांग्रेस के तीन नेताओं को कारण बताओ नोटिस दिए गए थे, तब उनसे उम्मीद थी वे इनका जवाब देंगे। लेकिन उक्त तीन में से एक महेश जोशी ने कहा है कि उन्हें नोटिस आज ही मिला है और वह 26 अक्टूबर तक इसका उत्तर देंगे।

यह देखना रोचक होगा कि अनुशासन समिति और कांग्रेस नेतृत्व इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देते हैं, एक बात तो स्पष्ट है कि हताश अशोक गहलोत इस मामले को लम्बा खींचने की कोशिश कर रहे हैं और जितना अधिक संभव हो, उतने समय तक मुख्यमंत्री के बंगले में रहना चाहते हैं।

जमीनी गणित दर्शाती है कि यदि गहलोत पार्टी को विभाजित करने की कोशिश करते हैं तो 12-13 से अधिक विधायक पार्टी छोड़कर नहीं जाएंगे। विश्लेषकों के अनुसार यह संख्या भी ज्यादा है।

गहलोत धमकी दे रहे हैं कि यदि उन्हें हटा दिया गया तो वह सरकार गिरा देंगे। वह और ज्यादा विधायकों का समर्थन पुनः प्राप्त करने के लिए समय लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सूत्र कहते हैं कि ऐसा हो नहीं पा रहा है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सोनिया दो घंटे पैदल चलीं

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर। ''भारत जोड़ो यात्रा'' के प्रति अपनी भावना की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति के रूप में, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कर्नाटक के मांद्या जिले में जक्कानाहल्ली तथा क्राद्या के बीच अपने पुत्र राहुल गांधी के साथ चलते हुये पद यात्रा में अपनी उपस्थिति दर्ज की।

- कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा कि, सोनिया सिर्फ 30 मिनट ही रूकने वाली थीं पर जनता के भारी उत्साह और समर्थन को देखकर वे दो घंटा तक यात्रा में रहीं और पैदल भी चलीं।

कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता तथा ए.आई.सी.सी. महासचिव जयराम

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

धर्मेन्द्र राठौड़ की अचानक घोषणा से ''पैलेस ऑन वील्स'' की बोर्ड बैठक में हड़कम्प मचा

धर्मेन्द्र राठौड़ चाहते थे कि, सरकारी आदेश की अनदेखी कर आर.टी.डी.सी. ''पैलेस ऑन वील्स'' का संचालन स्वयं करे

- बोर्ड के अन्य सदस्य, पर्यटन विभाग, वन विभाग और रोडवेज़ विभाग के प्रतिनिधियों ने ही आर.टी.डी.सी. के अध्यक्ष धर्मेन्द्र राठौड़ के प्रस्ताव की आलोचना की और प्रस्ताव पास नहीं होने दिया।
- विवाद का विषय है, कोविड के दौरान ट्रेन कैंसल होने के कारण, जी.एस.ए. (जनरल सेल्स एजेन्सीज़) को दिये जाने वाले ''रिफंड वाउचर्स''।
- धर्मेन्द्र राठौड़ के प्रस्ताव में पर्यटन विभाग को भारी नुकसान उठाये जाने की संभावना जताई गई थी बैठक के दौरान।
- आगे यह भी कहा गया था कि, जी.एस.ए. ''रिफंड वाउचर्स'' का इस्तेमाल करके मुफ्त टिकट लेकर भारी मुनाफा कमा सकती हैं।
- मुद्दा यह भी है कि, कैबिनेट की बैठक में प्राइवेट पार्टी को साथ लिए जाने के संबंध में जो आदेश पारित हुआ था उसके तहत अगर प्राइवेट पार्टी को जोड़ा जाता, तो न केवल राजस्व में वृद्धि होती बल्कि प्राइवेट पार्टी जी.एस.ए. को दिए गए रिफंड वाउचर्स व उनके दुरूपयोग पर भी कड़ी निगरानी रखती।

जयपुर, 6 अक्टूबर (का.सं.)। पैलेस ऑन वील्स ट्रेन, जिसकी सेवाएं करोना महामारी के कारण मार्च 2020 में बंद कर दी गई थीं, अब ढाई साल बाद पुनः शुरू की जायेंगी। समाचारों के अनुसार 8 अक्टूबर से जयपुर से इसका ''फेम टूर'' आरंभ किया जायेगा और 12 अक्टूबर से दिल्ली से इसकी सेवाएं पूरी तरह शुरू की जायेंगी। सूत्रों की माने तो 8 अक्टूबर को इस ट्रेन को स्वयं मुख्यमंत्री हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।

गौरतलब है कि 27 अगस्त को हुई कैबिनेट की बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया था कि पैलेस ऑन वील्स ट्रेन को ''भारत गौरव ट्रेन पॉलिसी'' के अधीन ''ऑपरेशन एंड मैंटिनैंस मॉडल'' के तहत शुरू किया जायेगा। पाठकों को बता दें कि ''ऑपरेशन एंड मैंटिनैंस मॉडल'' के तहत निजी पार्टी को निविदा में आमंत्रित किया जाएगा और पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पी.पी.पी.) मॉडल की मदद से इस ट्रेन सुविधा का संचालन होगा। इस नीति को लागू करने का मुख्य उद्देश्य यह था कि इससे इस ट्रेन सुविधा को ज्यादा मुनाफाजनक बनाया जा सके और राज्य व केंद्र सरकार ज्यादा राजस्व कमा सकें। उल्लेखनीय है कि पहले इस ट्रेन से पर्यटन विभाग को सालाना तीन करोड़ रु. की आमदनी हो रही थी, लेकिन निजी पार्टी से पार्टनरशिप के बाद आय सालाना आठ करोड़ रु. तक बढ़ने की संभावना जताई गई है।

अचंभे की बात है कि राजस्थान टूरिज्म डवलपमेंट कॉर्पोरेशन (आर.टी.डी.सी.), जो इस ट्रेन के संचालन के लिये मुख्य रूप से जिम्मेदार है, उसने निजी पार्टियों को आमंत्रित करने के लिये निविदा भी जारी नहीं की। इससे साफ जाहिर है कि कैबिनेट में

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ताईवान में अमेरिकी हथियार

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर। अमेरिका के वर्तमान एवं पूर्व अधिकारियों का कहना है कि अमेरिका ताईवान में हथियारों के बहुत विशाल जखीरे के भण्डारण के जबरदस्त प्रयास करने में लगा हुआ था ताकि चीन की भूमि से होने वाले हमले को हतोत्साहित करने के लिये, ताईवान को हथियारों एवं युद्ध-सामग्री से पूरी तरह भरे हुये

- अमेरिका ने ताईवान में हथियारों का भंडार बनाने की कवायद तेज कर दी है ताकि चीन के अचानक हमले की दशा में ताईवान अपनी सुरक्षा कर सके।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)